MR. SPEAKER : "If so" comes as a hypothetical question. This question has been answered a number of times today. I am passing on to the next question. It has already taken half an hour. Professor Samar Guha should take some more rest. He can go now.

Demand by Textile Industry for upward rivision of prices of controlled cloth

+

*332. SHRI SITARAM KESRI :
SHRI YASHPAL SINGH :
SHRI N. K. SOMANI :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the textile industry has made demands for the upward revision of prices of controlled varities of cloth ;

(b) if so, the reasons advanced for the revision ; and

(c) Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) Yes, Sir.

(b) The Indian Cotton Mills Federation have urged an increase in the prices of controlled cloth on account of increase in prices of cotton, wages, stores power, fuel, coal and dyes and chemicals and also due to increase in rates of interest and overhead charges.

(c) The matter has been referred to the Bureau of Industrial Costs and Prices.

श्री सीताराम केसरी : माननीय मंत्री महोदय ने कन्सल्टेटिव कमेटी में अपने भाषण के दौरान कहा था कि अभी टेक्सटाइल पर कीमत बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन स्टेटमेंट में वह कह रहे हैं कि परिस्थिति इस तरह की है कि जिस की वजह से यह सवाल ब्यूरो को सौंपा गया है कि प्राइस बढ़ाई जाय या नहीं कपड़े की। जहां तक मुझे मालूम है जो काटन की उपज पहले 62 लाख वेल्स होती थी वह अब 57 लाख वेल्स हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि काटन विदेशों से फिक्स्ड प्राइस पर इम्पोर्ट होती है। इसलिये मिल वालों को फिक्स्ड प्राइस पर दे कर वह कंज्यूमर्स को कंट्रोल प्राइस पर कपड़ा क्यों नहीं दे सकते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि जो काटन आप इम्पोर्ट करते हैं या जो काटन आप के पास है, चूंकि उस की प्राइस फिक्स्ड है इस लिये आप कपड़े के दाम नहीं बढ़ायेंगे ?

श्री ल० ना० मिश्र : कपड़े का मूल्य बढ़ाने का प्रश्न अभी नहीं है। माननीय सदस्य ने कन्सल्टेटिव कमेटी की चर्चा की। उस की चर्चा यहां नहीं होनी चाहिये थी। लेकिन मैं यह बात कहूंगा कि मैं ने कन्सल्टेटिव कमेटी में भी यह बात कही थी कि हम ने इस को ब्यूरो के पास भेजा है। जहां तक काटन के दाम की बात है, हम काटन कारपोरेशन के जरिये से खरीदते हैं। कपड़े पर हम बहुत कम मुनाफा लेते हैं शायद एक बेल पर एक रुपया। काटन कारपोरेशन के इस्टैब्लिशमेंट वगैरह पर खर्च करने के लिये वह लिया जाता है। काटन के दाम वैसे ही बढ़ गये हैं देश के भीतर। बाहर से काटन लाकर ला कर उस के दाम निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है।

श्री सीता राम केसरी : चूंकि कन्सल्टेटिव कमेटी का मंत्री महोदय का भाषण अखबार में निकला था इस लिये मैं ने उस की चर्चा की, नहीं तो न करता। जब कपड़े की कीमत बढ़ाते हैं, जिस की वजह से उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ता है, तब उपभोक्ता की परेशानियों को मदे नजर रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जो कपास आप बाहर से मंगाते हैं और जो काटन यहां मार्केट में बिकती है उस का जो कंट्रोल रेट है उस पर वह मिलों को बी जाती है, इस लिये क्या यह उचित नहीं है कि

जो प्राइस पहले से ही ज्यादा है उस को और न बढ़ाया जाये ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं ने कहा कि मिल वालों की कपास की कीमत बढ़ गई है, इस लिये दाम बढ़ गये थे । माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि सभी कपड़े की कीमत पर कंट्रोल नहीं है । कोर्स क्लाथ पर है जैसे धोतियां हैं, लांग क्लाथ है । इन पर ही कंट्रोल है, दूसरी चीजों पर नहीं है । मेरी राय यह है कि अभी कीमत बढ़ाने की परिस्थिति नहीं है । ब्यूरो से इस के बारे में पूछा गया है । ब्यूरो वाले इस को देखेंगे और समझेंगे कि उन की मांग सही है तो अपनी सिफारिश करेंगे । हम उस के बाद उस को देखेंगे कोई जरूरी नहीं कि उस की सिफारिश को हम मान ही लें । हम उस को एग्जामिन करेंगे , तब किसी निर्णय पर आयेंगे । लेकिन अभी उस की कीमत बढ़ाने की कोई बात नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा करने से हमारे विदेश व्यापार में भारत की साख बढ़ेगी या घटेगी ?

MR. SPEAKER : It is a matter of opinion.

SHRI N. K. SOMANI : Since May, 1968, when a trifling rise in the selling price was allowed by the Government of India, I want to know whether it is in their knowledge that the prices of cotton have shot up by 54 per cent, the prices of wages have gone up by 8 per cent and the overall index has gone up by 31 per cent—if this is not a fact, the Government can refute it—and, if this is a fact, whether under such circumstances, there is a single commodity or a product of any organised industry, textiles or otherwise, whose prices have been controlled and kept at 1968 level. My second question is in view of the compulsory closure of mills, in a block where a group of mills are going to close for a long time not only because the prices have now become impossible, but to con serve the availabilty of cotton, would the Government reconsider its policy of allowing some interim price rise as far as the controlled varieties are concerned and in view of the overall shortage of cotton, what is the final programme of imports of cotton for this particular year in addition to the 8.25 lakhs bales that they have already announced ?

SHRI L. N. MISHRA : So far as interim price rise is concerned, it is ruled out. We are not going to give any interim price rise. The whole question has been examined in greater detail.

SHRI PILOO MODY : Why ?

SHRI L. N. MISHRA : About imports of cotton, it is a fact that we have decided to import about 8.5 lakhs bales of cotton earler. Now, our present decision is to import more cotton because the indigenous production has suffered on account of floods, etc., in Maharashtra. Therefore, we are considering a proposal to import 13 lakhs bales of cotton from Sudan, UAR USA under PL 480 and other global sources.

About the rise in prices of cotton, it is a fact that there has been an alarming rise in the prices of cotton. I may give the figures. To-day's price is Rs. 2580 as against Rs. 1575 last year. The price rise has been alarming, but, at the same time, we are also going into its reasons. Also we have to consider the reaction that imports might have on the producers of cotton, the peasants and the cultivators. Therefore, when we come to a decision, we have to take into account the interests of the growers also.

श्री हुकम चन्द कछवाय : सरकार का रूप डाकिन की तरह पर है । जिन जिन चीजों पर पर डाकिन नजर डालती है वह या तो बीमार हो जाता है या मर जाता है । वैसी ही सरकार की नीति है । सरकार ने रुई का व्यापार अपने हाथ में लिया और राष्ट्रीय व्यापार निगम को दिया, फल यह हुआ है कि उस के दाम काफी बढ़ गये ; आप ने देखा होगा कि देश में अकाल

भी पड़ चुका है, वर्षा नहीं हुई और रुई बहुत कम हुई तो भी इतने दाम नहीं बढ़े थे जितने आज बढ़ गये हैं। हम को बतलाया गया है कि अकाल के समय जितने दाम बढ़े थे आज उससे ज्यादा बढ़ गये है। अब की देश में फसल भी काफी अच्छी है। जो दाम बढ़ गये है उस के कारण लोगों को रुई मिल नहीं रही है और कपड़ा उद्योग काफी मात्रा में बन्द होता जा रहा है। मेरे क्षेत्र में एक ताप्ती टेक्स्टाइल मिल है। उस में जो तीन हजार मजदूर काम करते थे वह बेकार हो गये हैं ऐसे ही और जगहों पर भी होता जा रहा है। क्या सरकार इस के लिये कोई उपाय करेगी जिस से कपड़ा उद्योग केवल उचित फायदा उठाये और हम को उचित दामों पर वह मिले तथा मजदूर बेकार न हों? कोई गारेन्टी देने के लिए सरकार तैयार है कि यह मिल बन्द नहीं होगी और मजदूर बेकार नहीं होंगे तथा कच्चा माल सस्ते दामों पर मिलेगा?

श्री ल० ना० मिश्र : माननीय सदस्य कहते हैं कि कपास की फसल बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है कि शायद माननीय सदस्य को धोखा हुआ है। कपास की फसल बहुत खराब है, खासकर उन इलाकों में जहां कपास ज्यादा होती है। जहां तक ताप्ती मिल का सवाल है या और किसी मिल का सवाल हो, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जो टेक्स्टाइल कारपोशन है उस से हम कहेंगे कि इस को देखे और अगर उस मिल को चलाने की जरूरत होगी तो उस को हम चलायेंगे। मिल के बन्द होने की कोई बात नहीं है। श्री सोमानी के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि 8 लाख बेल के बदले हम 13 लाख बेल कपास बाहर से मंगाना चाहते हैं। 60 हजार बेल हम यहां रिलीज कर रहे हैं ताकि बाजार पर असर पड़े और कपास के दाम नीचे आयें।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उत्तर नहीं आया। जो मिलें बन्द हो गई हैं उन्हें तत्काल चालू करने के लिए, उनको तत्काल राहत पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

श्री मु० अ० खाँ : जब जब किसान को अपनी मेहनत की कीमत मिलने का सवाल आता है तब तब इस किस्म की कोशिश की जाती है कि किसी सूरत से उनको जो कीमत मिलनी है उसको घटाया जाए। गल्ला और दूसरी चीजों की कीमतें जो किसान मेहनत करके पैदा करता है, बराबर गिरती जा रहा हैं जबकि उसकी जरूरियात की जो चीजें हैं, जो उसको बाजार में खरीदनी पड़ती हैं, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही है। अब काफी अर्से के बाद किसान को सही कीमत अपनी कपास की मिल रही है। काटन इम्पोर्ट करने के बाद सरकार ऐसी कोशिश तो नहीं करेगी जिससे जो मौजूदा कीमत कपास की किसान को मिल रही है, वह कम हो?

अध्यक्ष महोदय : यह कपड़े के भावों के बारे में सवाल है।

श्री मु० अ० खाँ : कपास से ही तो कपड़ा बनता है।

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने बताया है कि पंद्रह सौ से पच्चीस सौ कीमत हो गई है। हमें देखना होगा कि कपड़ा बना कर उसको हम बाहर एक्स्पोर्ट भी करें। अगर कास्ट आफ प्रोडकशन इतनी ज्यादा बढ़ गई और इस कारण से हमारा एक्स्पोर्ट घट गया तो यह राष्ट्र हित के लिए अच्छी बात नहीं होगी। किसान को उचित कीमत मिले, इस में कोई दो रायें नहीं है। हम चाहते हैं उसको उचित कीमत मिले। लेकिन पंद्रह सौ से पच्चीस सौ एकाएक हो जाए, तब चिन्ता भी थोड़ी सी हो जाती है।

SHRI S. KUNDU : Sir, the Minister, in reply to a question earlier said that they are not contemplating to raise the prices of the controlled cloth. But later on when there was a demand by Mr. Somani the Minister very cleverly corraborated the demand by saying that there has been alarming rise in prices and then he said he has referred the question to the Bureau of Cost and Prices. I would like to know specifically from him that even though this Bureau of Cost and Prices were to recommend that the prices of cotton cloth will go up or will be revised upward, will the Minister tell us firmly that in no circumstances he is going to revise upward the prices of textiles and controlled cloth ?

SHRI L. N. MISHRA : As I said earlier we have referred the question to the Buaeau of Industrial Cost and Prices. On receipt of report from them, we shall examine them. It is not obligatory on the part of the Government to accept the recommendations of the Bureau or the Tariff Commission. It is for the Government to consider the situation and come to a decision. About the price of raw cotton, we are rather happy, they are getting good price ; but some balance has to be struck and the question is how to maintain that balance.

SHRI S. KUNDU : There is no replv to my question. You said earlier, you are not going to increase the price of cotton cloth ; now you say, you will examine it. You should give a categorical reply.

श्री स० मों० बनर्जी : यह सही बात है कि चाहे पहनने का कपड़ा हो और चाहे ओढ़ने का और चाहे कफन का कपड़ा हो, सब के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जितनी कोशिश आप कम करने की कर रहे हैं, उसका उलटा ही असर हो रहा है। दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका कारण यह भी है कि काफी जो सूती मिलें हैं, वे बन्द हो गई हैं मिसमैनेजमेंट की वजह से या दूसरे कारणों से या उन्होंने इस वास्ते उनको बन्द कर दिया है ताकि और कसेंशंज गवर्नमेंट से ले सकें। जो मिलें चलने लायक है, जिन की मशीनरी काफी अच्छी है, क्या टैक्टाइल कारपोरेशन उन मिलों को लेने के लिए तैयार है ? यदि है तो कितने कारखाने अभी वह लेने वाला है ?

श्री ल० ना० मिश्र : टैक्सटाइल कारपोरेशन बीमार मिलों को लेने के लिए बनाया गया था। अभी तक वह 23-24 मिलों को ले चुका है। उन में से 12-13 की हालत काफी अच्छी हो गई है, उन में मुनाफा होने लग गया है। बंगाल की बारह मिलें बन्द पड़ी हुई हैं, यह भी एक चिन्ता की बात है। इस कारण वहाँ बेकारी भी बढ़ गई है। करीब पंद्रह हजार लोग बेकार हैं। बंगाल की मिलों को कैसे चलाया जाए, यह भी सोचना होगा। एक बात और भी है। जो पूंजी लगाई जाती है उसको 51 फीसदी तो हम देते हैं और 49 फीसदी स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार हो जाती है, हम आगे बढ़ते हैं। उतर प्रदेश में कानपुर शहर में तीन मिलें ली गई है और एक और मिल लेने की बात सोची जा रही है। जहां तक कीमत बढ़ने की बात है इस में कोई भ्रम नही होना चाहिए कि हम कीमतें बढ़ना नहीं चाहते हैं कपड़े की कुंडू साहब को सन्तोष नहीं हुआ लेकिन जब ब्यूरो की रिपोर्ट भी आयेगी तो जैसे मैंने कहा कि इसकी जांच की जाएगी इसको हम एग्जैमिन करेंगे और देखेंगे और अगर जरूरी हुआ तो बढ़ाएंगे और जरूरी नहीं हुआ तो नहीं बढ़ाएंगे।

श्री स० मों० बनर्जी : कफन के कपड़े के दाम नहीं बढ़ने चाहिए।

SHRI PRABODH CHANDRA : May I know whether it is a fact that the STC charges much higher prices for the imported cotton from the mills than is warranted by the business standards ?

SHRI L. N. MISHRA : The STC does not deal in cotton at all. The Cotton Corporation of India deals with it. It came into existence about five or six months ago

and it dealt with this. The STC has nothing to do with it. Even the Cotton Corporation of India does not import cotton directly. There are agents on its behalf who do so. We do not make any profit-on it. Perhaps, some commission is the original people who were importing cotton earlier. Propobably, it is one rupee per bale or some thing like that. About 25 per cent goes for the establishment charges of the CCI and the balance 75 per cent goes to the agents, sub-agents etc. There is no question of making any profit so far as cotton is concerned.

SHRI LOBO PRABHU : It is our sad experience that Government succeed in increasing only prices. They cannot increase anything else.

Now, there are two factors which have contributed to this recent increase in prices. We must realise that the quantity of cotton available both indigenously and from import is nearly the same. Why has the price risen then ? My first question is this. Is this not due to the operations of the CCI ? The hon. Minister has just said that the import has not made any impact on prices. But what about the indigenous purchase ? Now comes my second question. The hon. Minister has introduced mills in the public sector from the private sector. Is it not a fact that they are buying above the rate offered by private mills, and there by putting up the prices ? So, these are two very important questions. I assert that Government are contributing to the rise in prices. What has the hon. Minister to say on this ?

SHRI L. N. MISHRA : The Cotton Corporation has nothing to do with the indigenous production of cotton.

SHRI LOBO PRABHU : It has.

SHRI L. N. MISHRA : Our assessment was that we would have 62 lakhs bales of cotton this year indigenously. But the production has come up to only 57 lakhs, mainly because of floods in Maharashtra. About the rise in price of cotton, it is mainly because of the fall in production of indigenous cotton. There is no question of creating any trouble because of the CCI or the mills managed by ths National Textile Corporation of India. The public sector is not to be blamed at all. The hon. Member says that there is nothing except rise in prices. I would request him to look into the production figures also. Textile production has gone much higher than what it was two or three years ago.

SHRI LOBO PRABHU : What about the mills in the public sector ? Are they not buying above the rate offered by the private mills ?

MR. SPEAKER : I thought that the men who came from the Civil Service were a little calm.....

SHRI LOBO PRAHU : We are clam, but we expect also a certain response.

MR. SPEAKER : If he also does this, then I do not blame the others at all.

Action against Industrial Houses failing to fulfil Export Obligations

+

*334. SHRI RABI RAY :
SHRI MANIBHAI J. PATEL :
SHRI SHIVA CHANDRA JHA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have decided to penalise thosed firms which fail to fulfil the export obligations undertaken in return for licences for the import of capital goods or foreign collaboration agreements ;

(b) if so, the deatails thereof ;

(c) whether Government have got reports about firms which failed to meet export obligations ; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI